**भारत सरकार**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

# (न्याय विभाग)

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1013**

**जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012 को दिया जाना है**

**vf/kfu.kZ;ksa dks osclkbV ij viyksM fd;k**

**tkuk**

**1013- Jh ,uñ ckyxaxk %**

D;k **fof/k vkSj U;k;** ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd %

¼d½ D;k ljdkj us ns'k ds fofHkUu U;k;ky;ksa ds vf/kfu.kZ;ksa@fu.kZ;ksa dks mudh viuh osclkbV ij viyksM djkus dk fu.kZ; fy;k Fkk (

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugha] rks blds D;k dkj.k gSa ( vkSj

¼x½ ,sls fu.kZ; ij ljdkj dh D;k izfrfØ;k@izR;qÙkj gS \

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री (डा. अश्वनी कुमार)**

**(क) से (ग) :** ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, सरकार ने न्यायालय के निर्णयों/आदेशों की आनलाइन उपलब्धता सहित ई-सेवाओं की संख्या को उपलब्ध करने का विनिश्चय किया है । देश में उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों/िवनिश्चयों को वेबसाइट http://judis.nic.in पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है । ये उच्चतम न्यायालय और अधिकतम उच्च न्यायालयों की वेबसाइट पर भी हैं । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वेबसाइटें, 14,249 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के भाग के रूप में विकसित की जाएगी । इन न्यायालयों का कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है । ई-सेवाएं, कंप्यूटरीकृत पूरा होने के पश्चात्, निर्णयों/आदेशों की आनलाइन सहित आरंभ की जाएगी । 31 अक्तूबर, 2012 को 11,165 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को पहले ही कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है ।